हर साल हजारों लोग अफ्रीका के सबसे ऊँचे पर्वत माउन्ट कीलीमंजारो के शिखर पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। अब, एक नई हाईस्पीड इन्टरनैट सेवा की बदौलत, तंजानिया के 19341 फुट ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते हुए लोग फोटो शेयर कर पाएंगे और ई-मेल चैक करने के साथ -साथ इन्टरनैट सार्फिंग कर सकेंगे। आगामी कुछ समय तक, चढ़ते समय 12205 फीट की ऊंचाई तक वाई फाई सेवा मिलेगी और सरकार को उम्मीद है कि वर्ष के अंत तक शिखर पर भी इन्टरनैट सेवा उपलब्ध हो जाएगी। तंजानिया के सूचना व प्रसारण मंत्री ने बताया कि, तंजानिया के दूर संचार निगम ने यहां फाइबर -ऑप्टिक ब्रॉडबैंड नेटवर्क स्थापित किया है। हाईस्पीड इंटरनैट सर्विस से पर्वतारोहण ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा क्योंकि अब यात्रियों को आसानी से मदद मिल सकेगी। कीलीमंजारो पहला पर्वत शिखर नहीं है जहां इंटरनैट सेवा है। इससे पहले वर्ष 2020 में माउन्ट एवरैस्ट पर भी 5 जी नैटवर्क शुरु किया गया था। तंजानिया के सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि, पूर्व में इन्टरनैट के बिना यहां चढ़ाई करना खतरनाक होता था। ज्ञातव्य है कि, माउन्ट कीलीमंजारो तंजानिया की आय का बड़ा जरिया है और वर्ष 2019 में राज्य की कुल जी.डी.पी. का 17 प्रतिशत इसी की देन थी। हर वर्ष लगभग 50,000 लोग, पहाड़ की तलहटी में स्थित कीलीमंजारो नैशनल पार्क घूमने आते हैं और करीब 35,000 लोग इस पर्वत शिखर पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। कीमीमंजारो की खास बात यह है कि, यह किसी पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है, बल्कि तंजानिया व कीनिया के मैदानों से उठने वाला विश्व का सबसे बड़ा "फ्री स्टैण्डिंग माउन्टेन" है। इसका शिखर बर्फीले ग्लेशियर्स से घिरा हुआ है। लेकिन वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी है कि, जलवायु परिवर्तन की वजह से अगले दशक तक ये ग्लेशियर पिघल जाएंगे।

सी.बी.आई. ने मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की तलाशी ली

मनीष सिसोदिया ने कहा कि, सी.बी.आई. ने मेरे खिलाफ पूरा जोर लगा लिया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला

- **सी.बी.आई. ने दिल्ली की नई शराब नीति में हुये कथित भ्रष्टाचार के मामले में एक बार फिर मनीष सिसोदिया के खिलाफ छापा मारने की कार्रवाई की है।**
- **इससे पहले गत 19 अगस्त को भी सी.बी.आई.ने सिसोदिया के घर एवं उनसे जुड़े परिसरों पर भी छापे मारे थे।**

नई दिल्ली, 30 अगस्त (वार्ता)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया के पंजाब नैशनल बैंक के लॉकर की मंगलवार को तलाशी ली।

सी.बी.आई. सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी ने नई आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं को लेकर बैंक की गाजियाबाद शाखा का दौरा किया।

तलाशी के कुछ घंटे पहले सिसोदिया ने ट्वीट किया, सी.बी.आई. हमारे बैंक लॉकर को देखने आ रही है। गत 19 अगस्त को मेरे घर पर 14 घंटे की छापेमारी में कुछ नहीं मिला।

सिसोदिया ने दावा किया,लॉकर में भी कुछ नहीं मिलेगा। सी.बी.आई. आपका स्वागत है। मेरा परिवार जांच में पूरा सहयोग देगा। लॉकर में मेरी पत्नी और बच्चों के गहने और कुछ अन्य सामान हैं।

गौरतलब है कि सी.बी.आई. ने 19 अगस्त को सिसोदिया के आवास पर छापा मारा था। जांच एजेंसी ने अभी तक यह खुलासा नहीं किया है कि उन्हें उसके घर से कोई सबूत मिले या नहीं।

विशेष सत्र के दौरान दिल्ली विधानसभा में उपमुख्यमंत्री के आवास पर सी.बी.आई. की छापेमारी का मुद्दा भी गूंज उठा। सिसोदिया ने सदन को बताया कि भारतीय जनता पार्टी सी.बी.आई. के छापे से उन्हें डराने की कोशिश कर रही है।

सत्र के दौरान दिल्ली विधानसभा में भाजपा विधायकों ने हंगामा किया और सिसोदिया को उनके पद से बर्खास्त करने की मांग की जबकि आप विधायकों ने विधानसभा परिसर में देर रात तक विरोध प्रदर्शन किया तथा उपराज्यपाल के खिलाफ सी.बी.आई.-ई.डी. जांच की मांग की।

सिसोदिया ने विधानसभा के दो दिवसीय सत्र के पहले दिन कहा,भाजपा नई आबकारी नीति को लागू करने में करोड़ों रुपये के घोटाले का दावा कर रही है जबकि मेरे घर तलाशी के लिए आए सी.बी.आई. अधिकारियों ने बताया कि यह सिर्फ एक करोड़ रुपये की जांच है।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि, हमने भाजपा के सभी सवालों का जवाब दिया अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा की बारी है, वह तीन घोटालों पर देश को सवालों का जवाब दें।

सिसोदिया ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में तीन सवाल किए। उन्होंने कहा कि हमने भाजपा के सभी सवालों का जवाब दिया अब उनकी बारी है, वह तीन घोटालों पर देश को सवालों का जवाब दें। दूध-दही जैसी चीजों पर जीएसटी लगाकर प्रधानमंत्री के दोस्तों के लाखों-करोडो के कर्ज क्यों माफ़ किए गए? इसकी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच क्यों नहीं हुई। पूरे देश में विधायकों को खरीदने के लिए भाजपा के पास 6300 करोड़ रूपये कहां से आए? दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना के ऊपर खादी ग्रामोद्योग का चेयरमैन रहते हुए नोटबंदी के समय हुए 1400 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच कब होगी?

उन्होंने कहा कि भाजपा के पास अब कोई सवाल नहीं बचे तो उनके नेता अपने द्वारा बोले गए झूठी बातों का जबाव मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक्साइज में भाजपा के नेता पहले आठ हजार करोड़ रुपये के घोटाले का राग अलाप रहे थे वो झूठ साबित हुआ तो 1.5 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार का जुमला गाने लगे। उसके बाद बोले नहीं 1100 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। इसके बाद 144 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात करने लगे। भाजपा के नेता इस फर्जी साजिश के पहले दिन से ही अपनी बातों को झूठा साबित कर रहे हैं और अपने झूठ का जबाब मांग रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा के सारे सवाल झूठे और मनगढ़ंत हैं। मेरे घर सीबीआई भेजी गई, 14 घंटे तक सीबीआई ने खोजबीन और पूछताछ की।

दिल्ली एन.सी.आर. देश का सबसे अधिक दुर्घटनाओं वाला क्षेत्र

दिल्ली में दुर्घटनाओं की दर देश में सर्वाधिक 20.03 प्रतिशत है इसके बाद 18.2 प्रतिशत के साथ मुंबई दूसरे स्थान पर है

- **इको इंडैक्स सर्वे-2022 के अनुसार देश के अधिकांश हिस्सों, विशेषतः चेन्नई में सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण आवारा जानवर हैं।**

नई दिल्ली, 30 अगस्त (वार्ता)। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र- दिल्ली-एन.सी.आर. देश में सबसे ज्यादा दुर्घटना संभावित शहरों में से एक है, जहाँ सबसे ज्यादा संख्या में दुर्घटनाएं होती हैं। वाणिज्यिक राजधानी मुंबई दूसरे स्थान पर है।

हाल में किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं वाहन चालकों की लापरवाही से हुईं। हालांकि जानवरों का सड़क पार करना, उबड़खाबड़ सड़क, गड्ढे, रैश ड्राईविंग और नशे में वाहन चलाना दुर्घटना के अन्य कारण हैं।

एको एक्सीडेंट इंडेक्स 2022 के अद्धवार्षिक सर्वेक्षण में बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, और मुंबई सहित मुख्य मेट्रो शहरों में हुई दुर्घटनाओं का विवरण दिया गया है। दिल्ली में दुर्घटना की दर 20.3 प्रतिशत है जबकि मुंबई में दुर्घटना दर 18.2 प्रतिशत है। इन दुर्घटनाओं के कारण भी दोनों शहर में एक समान हैं।

सभी मेट्रो शहरों में, बेंगलुरू में स्थिति सबसे अच्छी थी और यहां दुर्घटना दर 16 प्रतिशत है। इसके अलावा, चेन्नई में दुर्घटना की दर 18.6 प्रतिशत और हैदराबाद में दुर्घटना की दर 18.5 प्रतिशत है।

सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण आवारा जानवर है। खासकर चेन्नई में जानवरों के कारण सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं तीन प्रतिशत दर्ज हुईं। दिल्ली और बेंगलुरु में यह दो प्रतिशत थी। मेट्रो शहरों में कुत्तों के कारण 58.4 प्रतिशत दुर्घटनाएं हुईं, जिसके बाद 25.4 प्रतिशत दुर्घटनाएं गाय के कारण हुईं। आश्चर्यजनक बात यह है कि चूहों के कारण 11.6 प्रतिशत दुर्घटनाएं हुईं।

भारतीयों के लिए भी अन्तर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसैंस प्राप्त करना सुलभ होगा

देश के सभी राज्यों में जारी होने वाले ड्राइविंग लाइसैंस एवं ड्राइविंग परमिट भी एकसमान होंगे

- **इस मामले में केन्द्र सरकार ने गत 26 अगस्त को अधिसूचना जारी कर दी है।**
- **इंटरनैशनल परमिट जारी करने में भारत के समक्ष कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि 1949 में ही जिनेवा कन्वैंशन में भारत इससे संबंधित करार पर हस्ताक्षर कर चुका है।**

नई दिल्ली, 30 अगस्त (वार्ता)। सरकार अपने नागरिकों को ज्यादा सुविधा प्रदान करने के लिए पूरे देश में एकीकृत ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर जिनोवा समझौते के तहत अन्तर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट-आई.डी.पी. जारी करेगी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नागरिकों यह सुविधा देने के लिए आई.डी.पी. जारी करने की अधिसूचना गत 26 अगस्त को जारी की है।

भारत पहले ही 1949 के अन्तर्राष्ट्रीय सड़क यातायात कन्वेंशन यानी जिनेवा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर चुका है इसलिए अन्य देशों के साथ पारस्परिक आधार पर इसे स्वीकार करने के लिए इस सम्मेलन की शर्त के अनुसार आई.डी.पी. जारी करना आवश्यक है। हमारे यहां अभी विभिन्न राज्यों के आई.डी.पी. का प्रारूप, आकार, पैटर्न और रंग एक नही है। इस कारण देश के अनेक नागरिकों को अन्य देशों में अपने-अपने आई.डी.पी. के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

मंत्रालय ने कहा कि इस संशोधन से पूरे देश में एक जैसी आई.डी.पी. जारी कर जिनेवा कन्वेंशन के अनुपालन में मानकीकृत किया गया है। आई.डी.पी. को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने के लिए क्यू.आर. कोड का भी प्रावधान किया गया है। नियामक प्राधिकरणों की सुविधा के लिए विभिन्न कन्वेंशनों और केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली,1989 में वाहन श्रेणियों की तुलना को भी शामिल किया गया है। हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी उपलब्ध है।

अगर गहलोत...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वे वसुंधरा, गहलोत की बेहद नजदीकी मित्र हैं।

अगर गांधी परिवार चाहता है कि राजस्थान में उनकी सरकार बनी रहे तथा तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सत्ता में कांग्रेस की वापसी हो जाये, तो गांधी परिवार को राजनैतिक रूप से सख्त कदम उठाने की जरूरत होगी।

माइक्रोचिप ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बन गया है।

ताईवान अत्याधुनिक चिप का विश्व का सबसे बड़ा निर्माता है और इसके ब्लॉकेड से माइक्रोचिप्स का निर्यात रुक सकता है जिसकी जरुरत मोबाइल फोन व ड्रोन के निर्माण में पड़ती है। इसके अलावा सुपर कम्प्यूटर्स, सैलुलर नैटवर्क्स और नए हथियारों के निर्माण में भी चिप की आवश्यकता होती है।

विश्व भर की टैक्नॉलजी कम्पनियां अत्याधुनिक चिप की आपूर्ति के लिए ताईवान सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी (टी.एस.एम.सी.) पर ही निर्भर है। यह वॉशिंगटन और चीन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि सैन्य टकराव हुआ तो विश्व के डिजीटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान होगा।

यह निर्भरता शांति बहाली में मदद कर सकती है। ताईवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी और ताईवान की अन्य चिप निर्माता कम्पनियों पर चीन की निर्भरता कम्युनिस्ट पार्टी को ताईवान पर हमला करने से रोकेगी। और अमेरिका की निर्भरता उसे ताईवान को और ज्यादा मदद देने को प्रोत्साहित कर सकता है। ताईवान के लोग इस कम्पनी "सेक्रड माउण्टेन" देश का रक्षक कह सकते हैं। चिप के लिए ताईवान पर निर्भरता खत्म करने के लिए चीन सेमीकंडक्टर्स पर भारी निवेश किया है पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नतीजों से खुश नहीं है।

के.सी.आर. नीतीश कुमार से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राष्ट्रवादी मुद्दे को चुना और गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों के साथ कुछ अपना कुछ समय बिताया तथा उन्हें कुछ वित्तीय सहायता भी प्रदान की।

लेकिन, जब वे बिहार जाने को हैं तो उनके मन में साफतौर पर केवल राजनीति ही है। जैसा कि ज्ञात ही है कि बिहार में इस समय विभिन्न दलों का गठबन्धन सरकार है, जो लोकसभा चुनावों के लिये एकजुट विपक्ष के लिये सम्भावित व्यवस्था को प्रदर्शित कर रही हैं।

तेलंगाना सी.एम.ओ. द्वारा जारी सरकारी प्रैस-विज्ञप्ति में भी कहा गया है, "इस अवसर पर दोनों मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा करेंगे।" के.सी.आर. ने एक जनसभा में तेलंगाना की जनता से कहा कि वे 2024 में "भाजपा मुक्त भारत" बनाने का संकल्प लें।

वस्तुतः नीतीश कुमार को एन.डी.ए. छोड़ने तथा भाजपा को पटखनी देने के खेल में, पर्दे के पीछे से के.सी.आर. की युक्तियों का सहयोग मिल रहा था। यह सब उनके द्वारा एक ऐसे राजनैतिक गठबन्धन को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा था, जो गठबन्धन उस भाजपा को टक्कर दे सके, जो किसी तरह रूकती दिखाई नहीं दे रही।

इस साल के शुरू में, आर.जे.डी. नेता तथा इस समय बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कुछ समय तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ हैदराबाद में गुजारा था। अगर टी.आर.एस. के सूत्रों का विश्वास किया जाये तो यह भी माना जा सकता है कि उस समय के.सी.आर. ने नीतीश कुमार से भी बातचीत की थी।

प्रसंगवश बता दें कि के.सी.आर. और उनकी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति संसद में मोदी सरकार का समर्थन कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें महसूस हुआ कि उनके अपने मैदान पर भाजपा उन पर हमलावर होती जा रही है, तो उन्होंने एकाएक यू-टर्न ले लिया था। एक आक्रामक विपक्षी नेता की भूमिका का निर्वहन करते हुये, के.सी.आर. ने मोदी के उन बयानों की सत्यता की जांच की और प्रधानमंत्री पर तीखे हमले किए। प्रधानमंत्री के पुराने बयानों को ढूंढ निकालने के बाद, के.सी.आर. ने मीडिया कॉन्फ्रेंसों में उनकी रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। उन्होंने रूपये की गिरती हुईकीमत, पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में वृद्धि के सम्बन्ध में भी प्रधानमंत्री से सवाल पूछे।

भाजपा, ने 2019 के लोकसभा चुनावों में 4 सीटें जीती थी तथा हाल ही में हुए हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा था। इस आधार पर, भाजपा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों तथा लोकसभा चुनावों के लिये स्वयं को चुनौती देने वाली प्रमुख पार्टी मानने लगी है। भाजपा तेलंगाना में अपना प्रभाव एवं पहुँच बढ़ाने के लिये, अन्य राजनैतिक पार्टियों के नेताओं को अपनी ओर खींच रही है तथा इसके साथ ही, तेलुंगू फिल्म स्टारों तथा खेलों से जुड़ी सुप्रसिद्ध हस्तियों को पार्टी में लाने की कोशिश कर रहीं है।

रिकॉर्ड के लिये बता दे कि के.सी.आर. बिहार के उन 12 श्रमिकों के परिवारों वित्तीय मदद भी करेंगे, जो अभी हाल ही में एक अग्नि दुर्घटना में हैदराबाद में मर गये थे। वे मृतकों के पारिवारिक सदस्यों को 5 लाख रूपये के चैक प्रदान करेंगे। प्रत्येक शहीद सैनिक के परिवार को के.सी.आर. 10 लाख रू. के चैक देंगे। इसी प्रकार की कवायद के अन्तर्गत, के.सी.आर. तथा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने गलवान पार्टी के संघर्षो में शहीद हुये दो जवानों के परिवारों के सदस्यों को 10-10 लाख रू. के चैक प्रदान किये थे।

कश्मीर के 64 नेताओं ने एक साथ कांग्रेस से इस्तीफा दिया

- **आज़ाद ने दावा किया है कि, कश्मीर कांग्रेस के 95 प्रतिशत नेता उनके साथ हैं।**

जम्मू, 30 अगस्त (वार्ता)। कांग्रेस के करीब एक दर्जन वरिष्ठ नेताओं के पार्टी से त्यागपत्र देने के एक दिन बाद जम्मू कश्मीर में पूर्व उप मुख्यमंत्री तारा चंद सहित 64 कांग्रेस नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के समर्थन में पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है।

तारा चंद और कांग्रेस नेताओं के करीबी वरिष्ठ नेता बलवान सिंह ने यहां पत्रकारों को बताया कि परिस्थितियों और कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व संकट के कारण इन लोगों ने त्यागपत्र दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान के आसपास की एक मंडली के लोग पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं।

पूर्व विधायक ने जम्मू प्रांत के 64 नेताओं और वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षिरत संयुक्त त्याग पत्र को पढ़ते हुए कहा, हम सभी का दशकों से चली आ रही पार्टी के साथ बहुत लंबा जुड़ाव था और हमने अपनी सारी ऊर्जा और संसाधनों को जम्मू और कश्मीर में पार्टी के विस्तार के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे साथ जो व्यवहार किया गया वह अपमानजनक था।

पत्र में कहा गया है कि पाटी अध्यक्ष सोनिया गांधी को हमारे नेता और संरक्षक गुलाम नबी आजाद ने एक पत्र में पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हमारा मानना है कि हमें भी कांग्रेस से बाहर आकर सकारात्मक राजनीतिक समाज के निर्माण में कुछ सार्थक योगदान देना चाहिए जहां लोगों को सुना जाता है और जवाब दिया जाता है।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने पांच दशक से अधिक समय के बाद कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने दावा कि जम्मू-कश्मीर में पार्टी के 95 फीसदी कार्यकर्ता, पंचायत सदस्य और कांग्रेस के जिला विकास परिषद सदस्य उनके साथ आ गए हैं।

गुलाम नबी आजाद के पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमले जारी हैं। उनका कहना है कि राहुल संगठन के लिए ठीक नहीं है, बल्कि वह केवल धरना के लिए बेहतर हैं। खास बात है कि शुक्रवार को अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम लिखे पत्र में भी आजाद ने वायनाड सांसद पर जमकर सवाल उठाए थे।

बाबरी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बैंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एक वृहद बैंच अयोध्या मामले में फैसला सुना चुकी है इसलिए अब इस मामले में कुछ नहीं बचा है। बैंच ने कहा कि "जो बात खत्म हो गई है उसे आप लगातार नहीं उछाल सकते है। हम सिर्फ एक पुराने मामले को उठा रहे है कुछ मामले बने रहते है कुछ खत्म हो जाते है। इसका प्रमुख विवाद 5 जजों की बैंच निपटा चुकी है। याचिकाकर्ता की भी मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादी के खिलाफ दायर याचिका भी खत्म हो गई है।

गरीब सवर्णों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पीठ ने मंगलवार को तय कर दिया कि आर्थिक मानदंडों के आधार पर उच्च शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में इकॉनॉमिकली वीकर सैक्शंस (ई. डब्ल्यू. एस.) अर्थात गरीब सवर्गों को दिये गये आरक्षण की संवैधानिक वैधता पर निर्णायक सुनवाई 13 सितम्बर से शुरू होगी।

यह बैंच निर्देशों के लिये संबंधित मामलों की सूची 6 सितम्बर को बनायेगी। बैंच में अन्य जज हैं- न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी, एस. रवीन्द्र भट्ट, बेला एम. त्रिवेदी तथा जमशेद बी. पार्दीवाला।

इस सुनवाई में, 2019 में 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता कसौटी पर रहेगी। सी.जे.आई. ने घोषणा की कि जनहित अभियान की याचिका उस प्रकरण की अगुआई करेगी, जिसमें 2019 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। इसके साथ ही, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के उस निर्णय के खिलाफ दायर किये गये मुकदमे की सुनवाई चलेगी, जिस निर्णय में आंध्र सरकार के उस निर्णय को रद्द कर दिया गया है जिसमें 2005 राज्य के मुस्लिम समुदाय के लिये उच्च शिक्षा एवं सरकारी नौकरी में आरक्षण दे दिया गया था।

ताईवान ने पहली बार चीन के खिलाफ फायरिंग की

- **ताईवान के सुरक्षाबलों ने चीन के ड्रोन पर फायरिंग कर दी। हालांकि यह फायरिंग केवल "वॉर्निंग शॉट्स" के तौर पर ही थी।**

ताइपे, 30 अगस्त। ताइवान की सेना ने मंगलवार को चीन के ड्रोन पर फायरिंग कर दी। ताइवानी सैन्य प्रवक्ता का कहना है कि यह वॉर्निंग शॉट्स थे। इसके साथ ही चीन और ताइवान के बीच तनाव का स्तर और बढ़ना तय है। यह पहली बार हुआ है जब ताइवान की सेना ने इतना आक्रामक कदम उठाया है। सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक यह ड्रोन ताइवानी नियंत्रण वाले एक द्वीप पर चीनी सीमा के करीब उड़ान भर रहा था। बताया जाता है कि ताइवानी सेना की फायरिंग के बाद ड्रोन वापस चीन की तरफ मुड़ गया। बता दें कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। पेलोसी के दौरे के समय ही चीनी विमान ताइवान के आसमान पर उड़ान भरने लगे थे। वहीं चीन अमेरिका को भी अंजाम भुगतने की धमकी देता रहा है। नैंसी पेलोसी के दौरे के बाद अमेरिकी सांसदों का एक दल भी ताइवान के दौरे पर पहुंचा था। इसके बाद चीन का गुस्सा और ज्यादा भड़क उठा था।

अगला डेढ़ महीना निर्णायक साबित ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- **कांग्रेस के लिये एक अच्छी अफवाह यह है कि, नया अध्यक्ष राहुल गांधी को पार्टी के रोजमर्रा के कामकाज से मुक्त कर देगा व राहुल अपने नेतृत्व प्रदान करने की भूमिका बेखटके निभा सकेंगे।**
- **पर एक सच यह भी है कि, राहुल व प्रियंका ने सोनिया गांधी का मन व सोच बनवा दिया है कि, अगर युवा नेतृत्व को मौका नहीं दिया गया तो, पार्टी में दोबारा जान फूंकना संभव नहीं हो पायेगा, अतः पार्टी के समक्ष दो ही विकल्प हैं या तो युवा नेतृत्व को मौका दें या पुराने नेताओं को ही ढोते रहें, जिनका जनता से संपर्क बहुत ढीला पड़ चुका है।**

सिद्धारमैया जैसे प्रदेश कांग्रेस नेता भी गुलाम नबी की तर्ज पर अपनी खुद की पार्टी शुरू कर पार्टी को पुनर्जीवित करने की गांधी परिवार की योजना को अप्रभावी कर सकते हैं।

पूर्व विदेश मंत्री शशि थरूर जैसे नेता सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि पार्टी के चुनाव जनता में उसके प्रति फिर से दिलचस्पी पैदा करेंगे। पार्टी अध्यक्ष का चुनाव होने की स्थिति में थरूर भी चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ अपने दावेदारी ठोक सकते हैं।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशांक गहलोत, जिन्हें पार्टी के शीर्ष पद के लिए गांधी परिवार की पसन्द बताया जा रहा है, इस मुद्दे को लेकर दोहरा रूख रखे हुए हैं। वह ना तो इस बात से इन्कार कर रहे हैं और ना ही स्वीकार कर रहे हैं कि वे पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़कर अपने से उम्र में काफी छोटे सचिन पायलट के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार हैं।

यह कहा जा रहा है कि गांधी परिवार के सदस्य चाहते हैं कि गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बने क्योंकि इससे पायलट के साथ किए गए उनके वादे को निभाने में मदद मिलेगी और गहलोत भी पार्टी में उनके लिए चुनौती नहीं बन सकेंगे। आज के भारत में जहां परस्पर संशय का वातावरण बढ़ रहा है, उसमें पार्टी को लोकतांत्रिक बनाने के गांधी परिवार के प्रयास को ना केवल आंशिक संशय बल्कि पूर्ण संशय के साथ देखा जा रहा हैं।

वास्तविकता यह है कि, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कुछ युवा नेता सोनिया गांधी को यह समझाने में सफल रहे हैं कि कांग्रेस को विस्तार करने का जरूरत हैं, क्योंकि अधिकांश सीनियर नेता ज़मीनी वास्तविकता से रूबरू नहीं हैं और पार्टी इसीलिए अपना आधार खोती रही हैं।

तर्क यह है कि पार्टी यदि देश के युवा को आकर्षित करने में विफल रहती है तो कांग्रेस अंत ना पंत एक भूतकाल की वस्तु बनकर रह जाएगी।

बताया जाता है कि सोनिया गांधी इस तर्क से सहमत है और कांग्रेस ने इसीलिए ऐसे कदम उठाने शुरू कर दिए है: जिनके परिणामस्वरूप पार्टी की संभावनाएं ऐसे वक्त में बढ़ सकती है जबकि वह एक ऐसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी का मुकाबला कर रही है जो यह सुनिश्चित करना चाहता है कि देश कांग्रेस मुक्त हो जाए और जिसे अपने इन प्रयासों को कमजोर ना होने देने के लिए येन-केन प्रकारेण कोई भी साधन-अपनाने से कोई गुरेज नहीं है।

अगला डेढ महीना कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी के कुछ नेता जो विरोधियों के सम्पर्क में है निश्चित रूप से गांधी परिवार के पार्टी को मजबूत करने के प्रयासों को कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे।

गांधी परिवार की कोशिश है कि कांग्रेस को इतना मजबूत बनाया जाए कि वह महात्मा गांधी के दौरान उभरी भारत की अवधारणा को नष्ट कर रहे संघ-भाजपा गठजोड़ का आक्रामकता से मुकाबला क सके।

कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं, उसके समर्थकों के विकल्प सीमित हैं या तो वे राहुल-प्रिंयका की पार्टी के पुनर्निमाण की कार्य योजना के तहत युवा व ऊर्जावान नेता को चुने या फिर उन्हें जो पार्टी वे राजनैतिक विरोधियों के साथ मिले हुए है। आगामी दिनों में कड़ा संघर्ष दिखेगा जो या तो कांग्रेस को फिर से उभार देगा या फिर खत्म कर देगा।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908